Volume: 4 Issue: 5 Pages: 39-41

भारत में SDG4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) प्राप्त करने में NAAC मान्यता की भूमिका: एक समीक्षा

[*1] डॉ वन्दना मिश्रा

[*1] PDF स्कॉलर इन ICSSR, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष शिक्षा विभाग, नेहरु ग्राम भारती (डीम्ड यूनिवर्सिटी) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 05/April/2025
Accepted: 07/May/2025

***Corresponding Author**
डॉ वन्दना मिश्रा
PDF स्कॉलर इन ICSSR, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष शिक्षा विभाग, नेहरु ग्राम भारती (डीम्ड यूनिवर्सिटी) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) में से SDG4 का उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में NAAC (National Assessment and Accreditation Council) की महत्वपूर्ण भूमिका है। NAAC संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान कर यह सुनिश्चित करता है कि वे शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशासनिक उत्कृष्टता प्राप्त करें। यह समीक्षा NAAC मान्यता की भूमिका का विश्लेषण करती है कि यह किस प्रकार भारत में SDG4 प्राप्त करने में योगदान देती है।

मुख्य शब्द: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG4, NAAC, सतत विकास ।

प्रस्तावना:

SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) का परिचय - SDG 4 (Sustainable Development Goal 4), संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसर बढ़ाना है। यह शिक्षा को व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति, और आर्थिक वृद्धि का आधार मानता है।

SDG4 के मुख्य लक्ष्य – सतत विकास गोल 4 के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखिति है -

1. सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा - 2030 तक, सभी बालक और बालिकाएं मुफ्त, समान, और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें।
2. बाल्यावस्था शिक्षा और अधिकार - 2030 तक, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और विकास के अवसर प्राप्त हों।
3. तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच - 2030 तक, सभी युवाओं और वयस्कों को तकनीकी, व्यावसायिक, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलें।
4. रोजगारोन्मुख कौशल विकास - युवाओं और वयस्कों में रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक कौशल का विकास करना।
5. लैंगिक समानता और समावेशिता - 2030 तक, सभी के लिए शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना, विशेष रूप से महिलाओं, वंचित समुदायों, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए।
6. आजीवन सीखने के अवसर -शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो लोगों को किसी भी उम्र में सीखने के अवसर प्रदान करे।
7. साक्षरता और अंकज्ञानता -2030 तक, सभी युवाओं और अधिकांश वयस्कों में पढ़ने-लिखने और गणना करने का कौशल विकसित करना।

   शिक्षा में सुरक्षित और समावेशी वातावरण - शिक्षा के लिए सुरक्षित, गैर-भेदभावकारी और प्रभावी सीखने के माहौल का निर्माण करना।

भारत में SDG4 प्राप्ति के प्रयास

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य SDG 4 के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। इसके तहत कई सुधार किए जा रहे हैं:-

- समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से शिक्षा में समानता को बढ़ावा।

- विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना।
- NAAC और NIRF जैसी एजेंसियों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।

चुनौतियाँ

- क्षेत्रीय असमानता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर।
- वित्तीय संसाधनों की कमी: सभी संस्थानों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव।
- लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बाधाएँ: कई वंचित समुदायों के बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने में कठिनाई।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि SDG 4 एक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान, और समाज को मिलकर काम करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए आधारशिला है। यदि शिक्षा नीति और गुणवत्ता-मानकों का सही ढंग से पालन किया जाए, तो भारत SDG 4 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकता है।

SDG4 के प्रमुख उद्देश्य: SDG4 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है:

1. समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता ।
2. शिक्षा में समावेशिता और भेदभाव रहित अवसरों को बढ़ावा देना ।
3. कौशल-आधारित शिक्षा और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम ।
4. शिक्षा में निरंतर सुधार के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का विकास ।

भारत में शिक्षा क्षेत्र के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं

- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय असमानता
- बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी
- उच्च संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध का अभाव
- छात्रों में उद्योग-केंद्रित कौशल की कमी

NAAC की मान्यता: उद्देश्य.

NAAC एक स्वायत्त निकाय है, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का मूल्यांकन और मान्यता करता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करना और सतत सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। NAAC की मूल्यांकन प्रक्रिया 7 प्रमुख मानकों पर आधारित है:

1. पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास
2. शिक्षा में नवाचार और शिक्षण-प्रक्रियाएं
3. अनुसंधान, नवाचार और विस्तार गतिविधियाँ
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीखने के संसाधन
5. छात्र सहायता और प्रगति
6. गवर्नेंस और नेतृत्व
7. संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तमता

NAAC मान्यता और SDG4 के बीच सम्बन्ध

1. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना:** NAAC मान्यता संस्थानों को उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रेरित करती है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। उच्च रेटिंग प्राप्त संस्थान अक्सर बेहतर पाठ्यक्रम, शिक्षक, और सीखने के संसाधन प्रदान करते हैं, जो SDG4 के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
2. **समावेशिता और समान अवसरों का प्रोत्साहन:** NAAC संस्थानों को शिक्षा में लैंगिक समानता, क्षेत्रीय संतुलन और सभी वर्गों के छात्रों के लिए अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह संस्थानों को छात्र सहायता कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति, और विशेष सहायता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।
3. **कौशल-आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा:** NAAC मान्यता प्रक्रिया में यह भी आंका जाता है कि संस्थान कितनी दक्षता से उद्योग-केंद्रित कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। यह छात्रों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देता है, जो SDG4.4 के लक्ष्य से मेल खाता है, जिसमें युवा और वयस्कों के कौशल विकास पर जोर दिया गया है।
4. **शिक्षा में सतत सुधार:** NAAC मान्यता केवल मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थानों को निरंतर सुधार और आत्ममूल्यांकन की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इससे संस्थान शिक्षा में नवाचार और गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में कार्य करते रहते हैं।
5. **शोध और नवाचार को प्रोत्साहन:** NAAC के मानक शोध और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करते हैं और नई खोजों के माध्यम से समाज की भलाई में योगदान देते हैं।

प्रभाव और चुनौतियां

हालाँकि NAAC मान्यता का प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं जो निम्नवत है-

- प्रक्रिया की जटिलता: छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों के लिए मान्यता प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
- संसाधनों की कमी: कई संस्थानों के पास बुनियादी ढाँचे और गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधन नहीं होते।
- मान्यता प्रक्रिया की सीमाएँ: केवल मान्यता प्राप्त करने के लिए कागजी सुधार करना और स्थायी सुधारों पर ध्यान न देना एक प्रमुख समस्या है।

सफारिशें

- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के संस्थानों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।
- NAAC मान्यता की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि छोटे संस्थान भी इससे लाभान्वित हो सकें।
- निरंतर मूल्यांकन और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाए।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले।

इस प्रकार, NAAC मान्यता के माध्यम से भारत SDG4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकता है

निष्कर्ष:

NAAC मान्यता भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है और SDG4 प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्रीय संस्थानों को संसाधनों और

सहयोग की आवश्यकता है। यदि संस्थान सतत सुधार और नवाचार की दिशा में निरंतर कार्य करें, तो NAAC मान्यता भारत के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने में और अधिक प्रभावी साबित होगी।

संदर्भ सूची:

1. भारत सरकार (2020)
2. पुस्तक का नाम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
3. प्रकाशक: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
4. यूनेस्को (2017)
5. पुस्तक का नाम: सतत विकास लक्ष्यों के लिए शिक्षा: अधिगम उद्देश्यों
6. प्रकाशक: यूनेस्को प्रकाशन, पेरिस
7. टिलक, जे. बी. जी. (2015),शिक्षा और विकास: भारतीय अनुभव से प्राप्त सबक, प्रकाशक स्प्रिंगर, नई दिल्ली
8. भट्टाचार्य, एस. (2013), शिक्षा के मूल सिद्धांत, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
9. शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) (2018), भारत में उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार
10. यादव, एस. के. (2019), भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन, श्री पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
11. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) (2020), स्वयं-मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए मार्गदर्शिका (महाविद्यालयों हेतु)
12. प्रकाशक: NAAC, बेंगलुरु
13. सिंह, आर. पी. (2017), भारत में उच्च शिक्षा: मुद्दे, चिंताएँ और नई दिशाएँ, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
14. संयुक्त राष्ट्र (2015), हमारी दुनिया को रूपांतरित करना: 2030 की सतत विकास कार्यसूची, प्रकाशक: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UNDESA), न्यूयॉर्क
15. अग्रवाल, पवन (2009), भारतीय उच्च शिक्षा: भविष्य की परिकल्पना, सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली